



भारत का गज़ीत The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

मई, दिल्ली, शुक्रवार, विदम्बर 26, 1986/प्राश्विन 4, 1908

No. 452] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1986/ASVINA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pagina is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

बिस दंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विवेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986

प्रधिसूचना

प्राप्तकर

सा. का. नि. 1111(ग्र).—यह आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराराधान के परिणाम और राजस्व भवित्वन को रोकने के लिए, भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच द्वितीय अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के द्वारा 1 में यथायेजित अनुसमर्थन दस्तावेजों का वही प्रगति, 1986 को आदान-प्रदान कर दिया गया है;

भत. आव. आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 90 और कम्पनी (साम) अस्तिकर अधिनियम, 1984 (1984 का 7) की द्वारा 24 का द्वारा प्रदत्त संवित्यों का व्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा दोहरा निवेश की है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जायें।

भारत गणराज्य की सरकार

ओर

कोरिया गणराज्य की सरकार

के बीच

दोहरे कराराधान के परिणाम द्वारा आय पर करों के संवेद्य में राजस्व अभिसमय को रोकने के लिए अभिसमय समझ करने की इच्छा से, भीष्मे लिख अनुसार हुई है;

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक भेद

यह अभिसमय उत्तर अवित्यों पर लागू होगा जो किसी एह भवा होने संविदाकारी राज्यों के लियाई है।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के प्रभाव आते वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक संविदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाए जाने वाले करों पर लागू होगा, जहाँ वे कर हिसी मों तरीके से लगाए जाते हैं।

2. कुल भाव अथवा भाव के तत्वों पर लगाए गए रामी कर, जिनमें अल अथवा अचल सम्पत्ति के प्रस्तुतण से होने वाले "अभिनामों एवं उद्धमों द्वारा भाव की गई मत्रावरी अथवा वेतनों की कुल रकम पर कर भी शामिल है, भाव पर कर माने जाएंगे।

3. जिस वर्तमान करों पर मह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) कोरिया के मामले में :

(1) आयकर;

(2) निगम कर; तथा

(3) निवासी कर;

(जिन्हें इसके बाद "कोरियाई कर" कहा जाएगा);

(ब) भारत के मामले में :

(1) आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई भी अधिनार शामिल है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रस्तुत लगाया जाएगा;

(2) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के मन्तरीत लगाया गया अतिकर;

(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

4. यह अभिसमय वर्तमान करों अथवा उनकी जगह लगाए जाने वाले करों के अतिरिक्त किसी भी समरूप अथवा सारतः वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सभी प्राधिकारी अपने अपने कराधार कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिमाणार्थ

1. इस अभिसमय में, जब तक कि संबंध में अन्यथा घोषित न हो :

(क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पदबन्ध के संबंध की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा कोरिया अभिप्रेत है;

(ख) "कर" शब्द के संबंध की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा कोरियाई कर अभिप्रेत है;

(ग) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है, जो कर प्रयोजनों के लिए सहा के रूप में माना जाता है;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भा सहा अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्धम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्धम" पदों से कम्पनी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्धम अभिप्रेत है;

(ज) कोरिया के मामले में "सामान्य प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, और भारत के मामले में नेतृत्व सरकार का वित्त मंत्रीलय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

(छ) "राष्ट्रिक" पद से किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता वाला कोई अविन और कोई भी कानूनी व्यक्ति, भागीदारिता संबंध अथवा अन्य सता जो एक संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून से इस प्रकार अपनी हैसियत प्राप्त करता हो, अभिप्रेत है;

(ज) "मन्तरार्थीय वातावात" पद में किसी ऐसे अलगाव अथवा वायुमान द्वारा कोई भी परिवहन अभिप्रेत है जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्धम द्वारा संचालित हो, निवाय उस स्थिति के जबकि अलगाव अथवा वायुमान दूसरे संविदाकारी राज्य के ही स्थानों के बीच चलाया जाता हो।

2. यह तक दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य द्वारा ही समय को लागू करने का संबंध है, किसी भी पद का जो इसमें परिमापित नहीं हो, जब तक संबंध में अन्यथा घोषित न हो, वही होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के मन्तरार्थ होता है :— (ग) इस अभिसमय के विषय ।

अनुच्छेद 4

प्राप्ति अधिकार

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिकार, निवास, प्रमुख अथवा मूल्य कारबल का स्थान, प्रबंध स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कासी के कारण वहां कर लगाया जा सकता है।

2. यहां पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत नीचे लियों नियमों के अनुसार तथ की जाएगी :

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उने एक स्थानी निवास गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थानी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उप संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके भाष्य उसके व्यक्तिगत भौतिक व्यवस्था विनियोग हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित है, नियम नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको दिसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थानी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उसमें से किसी भी राज्य में आदतन नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह संविदाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उसमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो, तो संविदाकारी राज्यों के सभी प्राधिकारी पारिषद्वारा सहमति द्वारा व्यवहार का नियम दर्शाये जाएंगे।

3. यहां व्यक्ति से विभ कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। संधेत जी स्थिति में संविदाकारी राज्यों के सभी प्राधिकारी पारिषद्वारा सहमति द्वारा इस प्रश्न का नियम दर्शाये जाएंगे।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अधिगमय के प्रयोगन के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निवित्त स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उद्यम का कारोबार समूर्ति: अधवा अभ्यतः खलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषता निम्नलिखित ग्रामिल होते हैं :

(क) प्रबन्ध का कोई स्थान;

(ख) कोई ग्रामा;

(ग) कोई कार्यालय;

(ज) कोई कारबाना;

(ङ) कोई ग्रामा, नेत अधवा गैस का कुद्रा, खदान अधवा ऐसा, कोई अन्य स्थान जहाँ से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं।

3. इसी प्रकार "स्थायी संस्थापन" पद में कोई भवन स्थल, कोई निमायि, संयोगन अधवा संस्थापन परियोजना अधवा उसके संबंध में पर्यावरणीय गतिविधियों भी ग्रामिल हैं, परन्तु वहाँ जहाँ इस प्रकार का स्थान परियोजना अधवा गतिविधियाँ नी महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती हैं।

4. इस अनुच्छेद के पूर्वांकी उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को ग्रामिल नहीं माना जाएगा :

(न) उद्यम के माल अधवा पर्य के केवल भण्डारण अधवा प्रदर्शन अधवा सुपुर्देगी के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग;

(ख) उद्यम के माल अधवा पर्य के केवल भण्डारण अधवा प्रदर्शन अधवा सुपुर्देगी के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना;

(ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संताधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अधवा पर्य का स्टाक रखना;

(घ) उद्यम के लिए माल अधवा पर्य का केवल क्रय करने अधवा मूल्का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थान रखना;

(ङ) उद्यम के व्यापार अधवा कारोबार में केवल विकापन देने, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अधवा अन्य कार्यों के प्रयोजनार्थ, जो अनन्य रूप से प्रारम्भिक अधवा सहायक किस्म के होते हैं, के लिए कारोबार का नियत स्थान रखना;

(घ) इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) से (ङ) में उल्लिखित किस्मों के अनन्यतः किसी संयोजन के सिए कारोबार का नियत स्थान रखना बताते कि संयोजन के परिणामसः कारोबार के नियत स्थान के समस्त किस्मेनाप्रारम्भिक अधवा सहायक किस्म के हों।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी स्पतन्त्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है, किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा [हो] तथा एक संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के नाम से संपत्ति करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करता हो, तो उन कार्यों के संबंध में, जिन्हें वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि कारोबार के किसी नियत स्थान के माध्यम से की गयी हों, तो कारोबार का यह नियत स्थान उस पैराग्राफ के कारण एक स्थायी संस्थापन भी होगा।

1. इस उद्यम के विवित उपबंधों में से किसी स्थायी संस्थापन होता महीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एंट्रेंट, अधवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एंट्रेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे अवित्त अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।

2. मात्र इन तथा वे जो कार्द कंपनी, जो एह तंदिवाकारी राज्य को नियासी हो, किंतु ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अधवा उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य को नियासी हो, अधवा जो उस दूसरे राज्य में (वहाँ किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अधवा अन्यथा) अपना कारोबार करती है, इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।

अनुच्छेद 6

प्रबल सम्पत्ति से आय

1. प्रबल सम्पत्ति से आय, पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2. "प्रबल संपत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार परिमापित किया जाएगा जहाँ मंदंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये ग्रामिल होंगे—प्रबल सम्पत्ति के उपमाध्यन के स्पष्ट में सम्पत्ति, कृषि और वन सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हैं, प्रबल सम्पत्ति को जोगेन के अधिकार और खनिज भण्डार, स्वोत तथा प्रयुक्ति संबंधी ग्रामिलों के संचालन के लिए अधवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अधवा नियत अवायगियों के अधिकार; पांत्र नीकाएं तथा विमान अवल संपत्ति नहीं माने जाएं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अवल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने अधवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाले आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध, किसी उद्यम की अवल संपत्ति से होने वाली आय, पर तथा स्वकल्प अवित्त सेवाओं के नियादन के लिए हस्तेमाल में आने वाली अवल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के आम पर केवल जीती राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थाई संस्थापन के माध्यम से कारोबार म करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थाई संस्थापन के कारण हुआ माना जा सकता है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध.म एहे हुए, जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थाई संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का ही लाभ समान जाएगा जिसे उसके द्वारा प्राप्त होने के तब अपेक्षा की जात जब वह उन्हीं या वैसी ही परिस्थितियों में, उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई नियंत्रित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम से पूर्णतया स्वकल्प रूप से कारोबार करता, जिसका यह, एक स्थाई संस्थापन है।

3. किसी स्थाई संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थाई संस्थापन के प्रयोजनों के लिए गए हों जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, जहाँ वे उम राज्य में किये गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित हैं अथवा अन्यत्र, और जिनकी स्वीकृति उम संविदाकारी राज्य के प्रपत्रे अन्तरिक कानूनों के उपबंधों के अन्तर्गत की जाती है, जिस में स्थायी संस्थापन स्थित है।

4. कोई नाम, भाव इन लिये स्थायी संस्थापन के कारण हुए नहीं माने जाएंगे कि उम स्थायी संस्थापन द्वारा उचम के लिए माल अथवा पर्याप्त बस्तुएँ खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से अवैतुवर्य निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विषद कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ आय अथवा लाभों में, आय की वे मर्दे शामिल हों, जिनका इस अभियन्त्र के अन्य अनुच्छेदों में अनुग्रह से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इन अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य ने उचम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से हुए लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "वायुयात संवालन" पद के अन्तर्गत वायुयात के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अवकेताग्रों (चार्टर्स) द्वारा वायुयात के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पण-धन, माल अथवा डाक का परिवहन, जिसमें अन्य उचमों की ओर से, ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की विक्री, किरणा—प्राधार पर वायुयात का प्रारंभिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उचम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसा संचालन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर, उस राज्य के प्रान्तरिक कानून द्वारा अन्यथा लगाये जाने वाले कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन-एजेंसी में भाग लेने होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 10

संविदाकारी उचम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उचम दूसरे संविदाकारी राज्य के उचम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उचम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उचम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवैतुवर्य में, दोनों उचमों के बीच उनके आणिंदिक अधिकारियों संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से मिल हैं, जैसी स्वतंत्र उचमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ, जो उन शर्तों के वहाँ नहीं की हाजिर में उन उचमों में से एक उचम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उचम के लाभों में सम्मिलित किए जा सकेंगे और तबनुसार करारेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है, जिस राज्य की लाभांश देने वाली कंपनी निवासी है, परन्तु यदि पाने वाला लाभों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर नीचे बताई गई रकम से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी लाभों एक ऐसी कंपनी है, जिसके पास लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी की पूंजी का प्रत्यक्षतः कम से कम 20 प्रतिशत भाग हो ;

(ख) अन्य सभी लाभों में लाभांश की सकल रकम का 20 प्रतिशत ।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के करारान पर कोई प्रभाव नहीं लालेगा जिसमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्राप्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ में भागीकार अर्ण—दावे नहीं हैं तथा अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिन पर वही करारान अवधारणा लागू होती है, जो उस राज्य के करारान कानून द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसपर वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी निवासी है, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक रैवार्ए सम्पत्ति करता है, और जिस धारणाधिकार के वारे में लाभांशों की शरायती की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 18 के उपबंध, ऐसी भी स्थिति हो, साकू होंगे।

5. जहां ऐसी कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की विद्यासाहिती, दूसरे संविदाकारी राज्य से नाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरे राज्य की वारा अद्वा किए गए लाभों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लाया, तब तक कि उस दूसरे राज्य के विवासी को ऐसा विए गए हैं जो अवधारणा सह किए गए विवासी को लाभों की अवधारणा की जाती है, वह उस ग्राम में स्थित किसी स्थायी संस्थान के अधिकारी को भावी रूप से मंत्रित करे, भावों उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लाया जाएगा और ताहे कंपनी के अन्तिम लाभों पर अविवित लाभ संवेदी कर लाया जाएगा, ताहे पक्ष किए गए लाभों अथवा अविवित लाभ पूर्ण रूप से अधिकारी की अधिक रूप से उत्तम राज्य में उत्तम होता वाले नाभ अवधारणा के रूप में ही हैं।

प्राचीन १२

ଛ୍ୟାଜ

1. एक संविदालारी राज्य में उत्पन्न होने वाले सभा द्वारा दूसरे संविदालारी राज्य के निवासी को श्रद्धा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदावारी राज्य में भी जिसमें वह उद्भव हुआ हो, और उस राज्य के कानून के शान्तमार कानून लगाया जा सकता है, ऐसिन यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर व्याज की रकम रकम के 15 प्रति से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपक्रमों के रहने सुए भी :

(क) अद्वीतीयाज, वास्तविक बैंकगंग बारोदार चाला नहे किसी वैक को अद्वा किया जाता है जो इनमे संविदाकारी राज्य का निवासी है और व्याज का क्रितमापी स्थापी है, तो उस संविदा कारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्तर देता है, सामाया गया कर व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(अ) जहाँ स्थान, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार अधिकारी उग राज्य के किसी राजनीतिक उग-मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण अधिकारी सेनेटर देश अथवा निर्यात-आयात बैंक को अश लिपि भारत के उग राज्य में कर जहाँ नमाया जाएगा तिसमें यह उत्पन्न होता है ।

4. इस अनुसन्धान में यथा-प्रयुक्त व्याज़ शब्द से यथित्रो है प्रत्येक प्रकार के अण संबंधी दायों से प्राप्त शाय, जोहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हैं अथवा नहीं और जोहे उन्हें अणपाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं, और आत्मोपर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त शाय और वंधपत्रों अथवा अण-पत्रों से प्राप्त शाय जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधन-पत्रों अथवा अण-पत्रों के गंबंद में प्रदान किये जाने वाले प्रीमियम और परस्कार शामिल हैं।

5. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपर्युक्त उम्म स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी स्थानी किसी संविधानकारी राज्य का निवारी होने से दूसरे संविधानकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से कानूनार बताता है, प्रथम उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस अद्यान्वये के बारे में व्याज अदा किया गया हो तो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थान अदाना निश्चित स्थान से भावी प्रथम संविधिव है। इस प्रकार के नामलों में अनुच्छेद 7 प्रथमा अनुच्छेद 18 के संबंध, जैसा भी सामग्रा हो, सामू होंगे।

६. व्याज किसी संविवाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाता, जब व्याज प्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक दप्तर, कोई स्थानीय प्राधिकरण अवश्य उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ व्याज प्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संतिवाकारी राज्य का निवासी हो अवश्य नहीं, संविवाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन स्थवरा निश्चित स्थान है, त्रिपक्ष संवेद में वह अप्प तिपा गदा भा जिव वर व्याज की अशक्यी की गई है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अवश्य निश्चित स्थान द्वारा बहुत किया जाता है, तब इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें नह स्थायी संस्थापन अवश्य निश्चित स्थान स्थित है।

प्रनाली १३

रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविधानकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविधानकारी राज्य के किस, निवासी को अदा को गई रायनियाँ और तकनीकों में विभिन्नों के लिए दी गई फीस पर उस कुपरे राज्य में कर लाया जायेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायिलियों और नक्नीकी सेवाओं के लिए दो गई फीस पर उस समिदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्यम हुई हैं और उक्त राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा नहीं, लेकिन यदि प्रान्तीकी, रायिलियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का द्वितीयी स्वामी है, तो इन प्रकार लगाया गया कर, रायिलियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुबोधे में यान्त्रिक "राष्ट्रियों" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक वृत्तियों के किसी भी कार्यालय जिसमें विनेमा फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रवारण में प्रयुक्त होने वाली किल्में अथवा टेप भी शामिल हैं, कोई पेटेन्ट, व्यापार-चिन्ह, डिजाइन अथवा माडल, ध्वनि, गुण फॉर्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा श्रीदोषिक, वॉयिजियक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिये अथवा श्रीदोषिक, वॉयिजियक अथवा वैज्ञानिक अनुबन्ध से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिकल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिव्रते हैं।

4. इस प्रत्युच्छेद में यथा-प्रयुक्त तकनीकी शेवाओं के निए फीस” पद गे प्रवन्धकारी, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की शेवाओं के लिये, जिनमें तकनीकी अथवा भान्य कामिकों की भेताओं भी व्यवस्था करना भी शामिल है, प्रतिकल के रूप में अदायगियां तरने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को भद्रायगियां करने तका प्रत्युच्छेद 15 में अंगित स्वतंत्र वैद्यकिक शेवाओं के लिए इनी व्यक्ति को गई भद्रायगियां से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गई भद्रायगियां अधिवैद हैं।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लाग, मर्ही होंगे, यदि रायस्टिट्यो अवधार तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का इतनागी स्वामी, जो एक संविदाकारी गव्य का निवासी है, और इससे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायस्टिट्यो अवधार तकनीकी सेवा तो के लिए फोस उद्घास होती है, वहां पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से अवधार वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से उस इस्से राज्य में अवधार विविधक सेवाएँ करता है, और जिस प्रधिकार, संघीय अवधार संसाधन के संबंध में रायस्टिट्यो अवधार तकनीकी सेवाओं के लिए फोग ग्राहक की जाती है, ऐसे स्थायी नंस्थापन अवधार निश्चित स्थान के साथ प्रमाणी रूप से संबंधित है। ऐसे भावज्ञों में, अनुच्छेद 7 प्रवदा अनुच्छेद 18 के उपर्युक्त, जैसा थी भाविता है, लागू होंगे।

8. एक संविदाकारी राज्य में रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फोस उद्योग हुई मानी जाएगी, जब रायलिट्यों और फोस प्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपर्युक्त, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस प्रदा करने वाले विक्री का, जहां वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिनके संबंध में अवायवियों करने का बहुत दिया गया था और उन स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा अवायवियों को जाती हों, तब रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस उन संविदाकारी राज्य में उद्योग हुई मानी जाएगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अवायवी और हितमानी स्नामी के बीच अथवा उन दोनों और अन्य आकित के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई को सही रकम ऐसे प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए, उनकी अवायवी की गई है, उस रकम से अधा जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तरुपी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध के बालं अनित्य अविष्ट रकम पर लागू होते हैं। ऐसे मामलों में, अधिक अदा की गई स्तर पर, इस अभिसमय के अन्वय उन्हें का डाता में रहते हुए, प्रत्येक अविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पुराने भविलास

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभासित अवल संपत्ति के अंतरण से अथवा ऐसी कंपनी के शेयरों के अंतरण से, जिसी परि-संपत्तियों में भुज्य रूप से अवल संपत्ति सम्मिलित हो, होने वाले अभिजाम, उन राज्य में कराधेय हो भक्तें जिसमें ऐसी तंपति स्थित है।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले भविलासों पर, जो उन स्थायी संस्थापन की अधिकारिक संपत्ति का एक हिस्सा है और जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिजाम पर, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में अधिकारिक सेवाओं के नियादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें एक स्थायी संस्थापन (प्रकाले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलास भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकें।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जलपोतों तथा बायुवानों के अंतरण से, जिन्हें ऐसा उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय मात्रावाल के अन्तर्गत परिचालित करता है तथा इस प्रकार के अल्पोत्ती सत्या बायुवानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति से प्राप्त अधिसाम्रप के बालं उस राज्य में कराधेय हो सकें।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलास, के बालं उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगे, जिसमें अन्तरणकर्ता एक निवासी है।

5. "अन्तरण" शब्द से अभिनेत है ऐसे संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार अन्तरण जिसमें संक्षिप्त मंपति स्थित है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाये

1. ऐसे अविट द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपावर्त्तिक भेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों विनायाद से प्राप्त आद पर के बालं उस राज्य में ही कर लगेगा जब तक कि उसे भवने कार्यक सापों का सम्बन्ध करने के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो। यदि उसके पास ऐसा निश्चित स्थान है, तो केवल उनीं आद पर ही उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसनों कि उस निश्चित स्थान के कारण हुई मानी जा सकती हो।

2. "अदावायिक भेवात" पढ़ में विशेष रूप स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक कलारमक, वैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षण संविदाकारी कार्यकलाप तथा विकिसकों, शल्व-विकिसकों, वक्षीलों, इंजीनियरों, बास्तुकारों, दन्त विकिसकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

परायित वैयक्तिक सेवाये

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों के प्रध्यवर्ती रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, जिसी नियोजन के संबंध में प्राप्त अवल, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर के बालं उसी राज्य में लगाया जा सकेगा, जब तक कि उसकी नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के द्वारे हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर के बालं प्रयोजनालिखित राज्य में ही हो लगेगा यदि:

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित "गिलो वर्व" अथवा "कराधान वर्व" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल भविलास 183 दिन तक प्रधायिक की प्रधायित अथवा अविवियों के नियोजन दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो ; और

(ख) पारिश्रमिक की अदावायी ऐसे नियोजन द्वारा अथवा की अवायवी से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा बहुत नहीं किया गया हो जो कि उस नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मात्रावाल के अन्तर्गत परिचालित करता है तथा इस प्रकार के अल्पोत्ती सत्या बायुवानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति से प्राप्त अधिसाम्रप के बालं उस राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17

निवेशकों भी फोस तथा उच्च स्तरीय प्रबन्धकों अधिकारों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कमानी के निवेशक मंडल के सदस्य की हैनियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निवेशक की फोस तथा इसी प्रकार की प्रधाय अवायवियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के उच्चस्तरीय प्रबंधकीय पद के अधिकारी के रूप में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त बैतन, मशहूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस व्यक्ति द्वारा राज्य में कर लग सकेगा।

५

प्रमुच्छेद 19

कलाकार और खिलाड़ी

1. प्रनुच्छेद 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक "संविदाकारी" राज्य के किसी निवासी द्वारा, लोक मनोरंजनकार्ता जैसे विषेषत, चलचित्र, देवियों अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा खिलाड़ी के पूर्ण में अपने वैकल्पिक कार्यों से, जिन्हें दूसरे संविदाकारी राज्य में किया जाता है, प्राप्त आप पर उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. जहाँ मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसके वैयक्तिक क्रियाकलायों के संबंध में प्राप्त आप रखने मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, प्रतिनु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो वहाँ उभे आप पर, प्रनुच्छेद 7 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ताओं "अथवा" खिलाड़ियों द्वारा एक संविदाकारी राज्य में किये गये क्रियाकलायों से प्राप्त "पारिश्रमिक अथवा लाभ, बैतन, मशहूरी तथा इसी प्रकार की आय" पर लागू नहीं होंगे, यदि उस राज्य में उनकी आय को, दूसरे संविदाकारी राज्य, किसी राजनीतिक उपर्युक्त अथवा उस के विसी स्थानीय प्राधिकरण की सार्वजनिक निधियों से संबंधित हो ने सहायता की जाती है।

प्रमुच्छेद 19

पेशन

प्रनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के प्रक्षेपण रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, पिछले नियोजन के प्रतिकाल में प्रदत्त वैधत तथा इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

प्रनुच्छेद 20]]

सरकार के कार्य]

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक राजनीतिक उपर्युक्त अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उस राज्य गवर्नर उपर्युक्त अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में आय की गयी पेशन से विश्व पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) निचापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा
(ii) सेवायें प्रदान करने के प्रयोजन माल के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

(ग) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक राजनीतिक उपर्युक्त अथवा दूसरे किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के लिए उस राज्य अथवा उपर्युक्त अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति की आय की गई अथवा उनके द्वारा निमित निधियों के लिए उसी द्वारा राज्य में कर लग सकेगा।

(घ) तथापि, ऐसी पेशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है और राष्ट्रिक है।

3. प्रनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध, एक संविदाकारी राज्य मध्यमा किसी राजनीतिक उपर्युक्त अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये कारबाह के तंत्रज्ञ में भी वही सेवाओं के बारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेशन पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, फोरिया के मामले में, वैकल्पिक कोरिया, नियांत्रिमायात वैकल्पिक कोरिया तथा फोरिया व्यापार संबंधित नियम द्वारा तथा भारत के मामले में भारतीय फिरव वैकल्पिक तथा भारतीय नियांत्रिमायात वैकल्पिक द्वारा और संविदाकारी राज्यों के सकाम प्राधिकारियों द्वारा मानवता प्रदान किये गये संगठनों द्वारा सभा उनकी सहमति से व्यवाह किये गये पारिश्रमिक अथवा पेशानों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे।

प्रनुच्छेद 21

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षियों द्वारा प्राप्त प्रदायणियों

1. किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दीरा करने के तुरन्त पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा या, और जो माल अपनी विद्या अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, उस दूसरे राज्य [में नियन्त्रिति पर कर से सूट प्राप्त होगी:

(क) उसके भरण-पोषण, विद्या अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके का गई अदायगियों; तथा

(ख) उस दूसरे राज्य में "किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "कराधान वर्ष" में जीसी भी स्थिति हो, रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर, जो उस लाभ और जाति सी हुआर कोरियाई वैकल्पिक अथवा उसके समसुल्य भारतीय मुद्रा से अधिक नहीं हो, वर्षते कि ऐसा-रोजगार उसके प्रध्यायन से सीधे संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के लिए किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ, केवल ऐसी अवधि तक के लिए उत्तम्य होगा जो विद्या अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित प्रध्याया साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पूर्णने की तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

प्रनुच्छेद 22

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोध छात्र

1. कोई व्यक्ति जो, दूसरे संविदाकारी राज्य का दीरा करने से तकाल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा या, और जो, उस दूसरे राज्य में सकाम प्राधिकारी द्वारा मानवता प्रदान किये गये किसी भी विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के आमंत्रण पर, उस दूसरे राज्य में ऐसी वैकल्पिक संस्थाओं के आमंत्रण पर, उस दूसरे राज्य में दोनों के प्रयोजनार्थ भासे हैं, ऐसे प्राध्यापन अथवा लोध कार्य के लिए, उस दूसरे राज्य में उसके पूर्णने की तारीख से लगातार दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, प्राप्त नहीं होगी।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य के प्राप्त आप पर लागू नहीं होगा, यदि इस प्रकार का शोध कार्य पूर्णतः किसी विभिन्न व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए किया जाता है।

मनुच्छेद 23

ग्रन्थ आय

‘एह गंविदाहारि राज्य के किसी निवासी की आय को उन मर्दों पर, जहाँ कहीं उद्भूत होती हो, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवार नहीं किया गया है, उस दूसरे राज्य में ही कर लग सकेगा।

मनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. कोरिया के निवासी के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा :

कोरिया से निम्न किसी भी देश में संदेश कर का कोरियाई कर के प्रति जाता जाना के रूप में क्षुट के संबंध में कोरियाई कर का कानून के जावंदों के अधीन रहते हुए (जिसका इसके मामाय सिद्धान्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता), भारतीय कानूनों के अनुरूप या इस अभिसमय के अनुसार संदेश “भारतीय कर (लाभार्ण के मामले में, उस लाभों के संबंध में देव कर को छोड़कर जिनमें से लाभार्ण अद्वा किया जाता है) प्रतवश अवयव कटीती हाया, भारत के अग्नी और औरतों से प्राप्त आय के संबंध में, उस आय के संबंध में संदेश दोहराई कर के प्रति जाता-जाना के रूप में अनुमति दी जाएगी। स्थापि, यह जाता-जाना, कोरियाई कर के उत्तरानुपात से अधिक नहीं होगा जो भारत के अद्वर के औरतों से प्राप्त आय का सम्पूर्ण आय पर कोरियाई कर के साथ हो।

2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, ‘संदेश भारतीय कर’ पद में भारतीय कर की उम रकम को मन्मिलित माना जाएगा जो भारतीय कर कानूनों के अनुसार उस स्थिति में संदेश होती, यदि उस पर भारत में आधिक विकास के संबंधन के लाए प्रोत्याहनों से संबंधित उन कानूनों के अनुभार भारतीय कर की क्षुट अवयव कटीत, प्राप्त नहीं होती जो इस अभिसमय पर हस्ताभर किये जाने की तारीख को लागू थे अवयव अन्य उपर्युक्त जिन्हें संविदाकारी राज्यों के संकर प्राधिकारियों की सहमति से उन कानूनों में संशोधन अवयव परिवर्तन के लिए भारत में बाब्द में लागू किया जाए परन्तु यह कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम :

(क) मनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभार्णों के मामले में ऐसे लाभार्णों की कुल रकम के 15 प्रतिशत के बाबाबर की रकम और, मनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभार्णों के मामले में ऐसे लाभार्णों की कुल रकम के 20 प्रतिशत के बाबाबर की रकम;

(ख) मनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित व्याज के मामले में, ऐसे व्याज की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम तथा मनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित व्याज के संबंध में ऐसे व्याज की कुल रकम की 10 प्रतिशत रकम; तथा

(ग) मनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित व्याज के मामले में, ऐसी रायस्तियों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम से अधिक नहीं होगी।

3. भारत के निवासी के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार अन्न प्रकार से किया जाएगा।

भारत से निम्न किसी भी देश में संदेश कर को भारतीय हर के प्रति जाता के रूप में क्षुट से संबंधित भारतीय कर कानून के जावंदों के अधीन रहते हुए (जिसका इसके सामाय सिद्धान्तों पर कार्य प्रभाव नहीं पड़ता) कोरिया के कानूनों के अनुरूप तथा इस अभिसमय के अनुसार कोरिया के अद्वर के औरतों में प्राप्त आय के संबंध में, प्रतवश अवयव कटीत। इस संदेश कोरियाई कर को (लाभार्णों के मामले में, ऐसे लाभों के संबंध में संदेश कर को छोड़कर जिनमें से लाभार्ण की अद्वायगी की जाती है) उस आय के संबंध में संदेश भारतीय कर के प्रति जाता के रूप में माना जाएगा। तथापि यह जाता भारतीय कर के उस मनुच्छेद से प्रधिक नहीं होती जो कोरिया के अंदर के औरतों से प्राप्त आय का संरूप आय पर भारतीय कर के साथ हो।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनों के लिए “संदेश कोरियाई कर” पद में कोरिया कर की उन रकम को मन्मिलित माना जाएगा जो कोरियाई कर कानूनों के अनुसार उत्तरास्थि में संदेश होती यदि उस पर कोरिया में आधिक विकास के संबंधन के लिए प्रोत्याहनों से संबंधित उस कानून के अनुसार कोरियाई कर की क्षुट अवयव करती है; प्राप्त नहीं होती जो इस अभिसमय पर हस्ताभर किये जाने की तारीख को लागू थे अवयव अन्य उपर्युक्त जिन्हें संविदाकारी राज्यों ने संकर प्राधिकारियों की सहमति से उन कानूनों में संशोधन अवयव परिवर्तन के लिए बाब्द में कोरिया में लागू किया जाए परन्तु यह कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम :

(क) मनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभार्णों के मामले में ऐसे लाभार्णों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम, तथा मनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभार्णों के बाब्द में ऐसे लाभार्णों की कुल रकम की 20 प्रतिशत रकम;

(ख) मनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित व्याज के मामले में, ऐसे व्याज की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम तथा मनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित व्याज के मामले में ऐसे व्याज की कुल रकम की 10 प्रतिशत रकम; तथा

(ग) मनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित रायस्तियों के मामले में ऐसी रायस्तियों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम से अधिक नहीं होगी।

मनुच्छेद 25]]

[सम्बन्धित

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी करावान अवयव तत्त्वविद्यी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से भी उस संबंधित अपेक्षाओं से निम्न अवयव कल्पकर हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैधी हो परिवर्तियों में लागू होती है अवयव हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के जिसी उच्च इतां दूसरे संविदाकारी राज्य में बदले जा रहे स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर महीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में ऐसे ही कार्यकलाप करने वाले उद्योगों पर लगाये जाने वाले कराधान से अपेक्षाकृत करम अनुकूल हों। इस उपर्युक्त कार्यकलाप का वह अधिक संविदाकारी राज्य के निवासियों को, लागिरिक प्रतिलिपा अवयव पारिवारिक उत्तराधिकारों के गारा कराधान के प्रयोजनावे कोई ऐसी अविकल्पत धूर, यहां तक कि गारा कराधान के लिए व्यापक, करता है जो वह स्वर्वके निवासियों को अनुप्रूप करता है।

3. इन मामलों में अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 12 का पैरा 7 अथवा अनुच्छेद 13 का पैरा 7 लागू होते हों, उन्हें छोड़कर द्वाज, रायर्टियों तथा अन्य अदायगियों जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उदाम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को की गई हों वे इस प्रकार के उदाम के केर लगते योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कहीं गर्मी पर कटीत पाने योग्य होंगी जैसे कि वे प्रथमोलिंगित राज्य के किंवित निवासी को अदा की गई हों।

4. एक संविदाकारी राज्य के उदामों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अतः दूसरे संविदाकारी राज्य है एक अथवा एक में अधिक निवासीयों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी प्रपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और संबंधित प्रोत्तेजियों में चिन्न अथवा अधिक कष्टकर हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उदामों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक प्रकार के तथा किस्म के करों पर लागू होते हैं।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कारों के कारण, उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह, इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपर्युक्त उपभारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह निवासी है अथवा, यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अन्दर आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह राष्ट्रिक है, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला, उस कार्यवाही की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के प्रतीकूल कराधान हुआ है।

2. सक्षम प्राधिकारी, यदि उसे आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपर्युक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो उसे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में निहित किसी भी समय सीमा के होते हुए भी कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयों अवश्य शांकाएं उत्पन्न हो तो, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेगे। वे ऐसे मामलों में भी दोहरे कराधान के अवश्यकता के लिए परन्तु परामर्श कर महीने जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं है।

4. पूर्वगत पैराग्राफ के अंतर्गत महसूनि के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी एक दौरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी ममतावैते पर पहुँचों के लिये विचारों का भौतिक आदान-प्रदान करना उपर्युक्त प्रतक हो तो ऐसा आदान-प्रदान करना एक आयोग के अधिकार से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दमावेज भी शामिल है) आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपर्युक्त अथवा संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों के उन उपर्युक्तों को लागू करने के लिये आवश्यक हों, जो इस अभिसमय के अधीन आने वाले करें से, खास तौर पर जानकारी अथवा इस प्रकार के करों के अपवर्जन को रोकने से संबंधित हैं जहाँ तक कि उनके प्रधीन लगाये जाने वाले कर इस अभिसमय के प्रतिकूल न हों। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिवर्चित नहीं है। एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जिस प्रकार उस राज्य के आंतरिक कानूनों के प्रत्यर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि सूचना, व्येषण करने वाले राज्य में मूल हर से गुप्त मानी जाती है, तब वह केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट की जाएगी जो उन करों के निपोर्यंग अथवा व्यूनी, उनके संबंध में प्रत्यर्गत अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्वारण में अन्तर्प्रैस्ट हों, जो इस अभिसमय के प्रियंक हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपरोक्त केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे इस सूचना का मार्वर्जनिक तौर पर न्यायालय की कार्यताहियों अथवा न्यायिक नियमों में प्रकट कर सकेंगे। नप्रत मार्वर्जनिक विचार-विमर्श द्वारा उन मामलों के संबंध में समुचित जरूरी तरीके तथा तकनीक विकसित करेंगे जिनके संबंध में सूचना का इस व्यापार का आदान-प्रदान किया जाएगा जिसमें, जहाँ उत्तिन हो, कर-परिहार के बारे में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपर्युक्तों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जो एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित के लिये बाध्य करे:

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रयोग से हटकर प्रशासनिक उपाय करना।

(ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है।

(ग) ऐसी सूचना देना, जिसमें कोई आंतरिक-व्यवसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गुप्त भेद अथवा आपारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो (आईए पब्लिक)।

अनुच्छेद 28

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकर्ता तथा कोंसल्टी अधिकारी

इस अभिसमय के अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विजेप जरूरतों के प्रावधानों के अंतर्गत, राजनयिक अभिकर्ताओं तथा कोंसल्टी अधिकारियों के रज्य तथा विभाग विजेप अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

श्रेणीनाम

1. इस अभिसमय के अभियुक्त को जाएगी लगा अभियुक्त दस्तावेजों का सिंगल में अथवा लंबव रूप आदान-प्रदान किया जाएगा।

यह अधिसमय अधिकृत के दस्तावेजों के आकात-प्रदान के सारीख के बारे 30वें तिथि प्रवर्तित होगा।

2. इस अधिसमय का :

(क) कोरिया में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में हम अधिसमय पर आद्यक्षर हुए हों उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिवार्यियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में, और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अधिसमय पर आद्यक्षर हुए हों उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने आते पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में,

प्रधान पड़ेगा।

(ब) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में हम अधिसमय पर आद्यक्षर हुए हों उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिवार्यियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अधिसमय पर आद्यक्षर हुए हों उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद मुश्य पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में, प्रधान पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

समाप्ति

यह अधिसमय अनिवार्यत काल तक लापू रहेगा, परन्तु संविदाकारी शर्यों में से कोई भी यज्ञ इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उस से पहले, राजनायिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी शर्य को समीक्षित का निवित नोटिस दे सके गा और ऐसी स्थिति में यह अधिसमय :

(क) कोरिया में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिवार्यियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अनवर्ती के पहले दिन को अथवा उनके बाद शुरू होने वाले कार्याधान वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में।

(ब) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद अनिवार्यियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में; और

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके प्रगते परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने आते पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में, निप्रभावी हो जाएगा।

जिसके साथ में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधीक्षमाधिकारी ने हम अधिसमय पर ज्ञाताधार किया है।

नई विली में आज वर्ष एक हजार तीन सौ पिंडासी के जुआई मास के 19 वें दिन को हिन्दी, कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में मूलतः दो-दो प्रतिवर्ती में किया गया, इसके सभी पाठ समाप्तनः प्रभावित होते। तीनों गाठों में विश्वास की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से कोरिया गणराज्य की सरकार की ओर से

(विष्वनाथ प्रसाद मिह)

विज्ञ संस्कृती

(बाबू अम्बेदकर महाराजा)

विदेश संस्कृती

प्रोतोकोल

आप पर करों के संबंध में बोहरे कार्याधान के परिवार और राजस्व अपवर्तन को रोकने के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुए अधिसमय पर हमाक्षर करने समय, अधोहस्ताकारी महमत हो गए हैं कि निम्ननिवित उपनियंष्ठ अधिसमय के प्रसिद्ध अंग होंगे।

1. अधिसमय के प्रतुच्छेद 2 के पैदाप्राप्त 3 के उपनियाराफ (क) के संबंध में, यह समझा जाता है कि अधिसमय उस कोरियाई रूप कर पर भी लागू होगा, अहो वह आपकर अथवा निराम कर के संदर्भ में प्रभावित होता है।

2. अधिसमय के प्रतुच्छेद 8 तथा 9 के प्रयोजनार्थ यह समझा जाता है कि :

(i) संवर्तराष्ट्रीय यातायात में बायुयान और पोर्टों के संचालन से संबंधित नियियों पर आज की भी ऐसे बायुयान और पोर्टों के संचालन में प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा; और

(ii) एक संविदाकारी यज्ञ के किसी उद्यम द्वारा चक्राए गए अन्तर्गत्राष्ट्रीय यातायात में बायुयान और पोर्टों के संचालन के संबंध में, उस उद्यम जो, यदि वह भारत का उद्यम है कोरिया में भूल्य वर्षता कर (बैलू एडेंट ईक्स) में भी छूट प्राप्त होगी, यदि कोरिया का कोई उद्यम है, तो कोरिया में भूल्य वर्षित कर के समान किसी कर में छूट प्राप्त होगी, जो इसके बाद भारत में भाग्या जा सकता है।

3. प्रतुच्छेद 9 के संबंध में यह समझा जाता है कि इसके पैदाप्राप्त 1 और 2 के उपनियंष्ठ उस कार्याधान वर्ष में अथवा उसके बाद चक्राए गए जहाजरानी परिवहन के संबंध में लागू होंगे, जिसमें संविदाकारी शर्यों अथवा उनके प्राधिकृत नामित-कर्तिकार्यों के बीच जहाजरानी परिवहन से संबंधित कोई कार्यर गम्भीर किया जाता है और प्रभावी होता है।

यह भी समझा जाता है कि जब तक संविदाकारी शर्यों अथवा उनके प्राधिकृत नामित-न्यूक्लियों के बीच जहाजरानी परिवहन से संवर्तित कोई कार्यर गम्भीर होता है, तब तक पैदाप्राप्त 2 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोर्टों के संचालन से अवित्त लाभों पर उस संविदाकारी यज्ञ में कर लगाया जाएगा, जिसमें इस प्रकार का संचालन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर उस यज्ञ के प्रालैंगिक कानून द्वारा अत्यधिक गम्भीर होगा, गण कर के 50 प्रतिशत से अधिक सही होगा।”

4. अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 और 4 के संबंध में यह समझा जाता है कि उन पैराग्राफों के उपबन्ध उन प्रथम पात्र वर्गों के लिये लागू होंगे जिनके लिए यह अधिसमय प्रभावी है ऐसित भविदाकारी वर्गों के समय प्राविकारी यह निर्वाचित वर्गों के लिए एक दूसरे में प्राप्तमर्यादा करने के लिए कागज ग्रहणशील बढ़ाई जाएगी।

जिसके माध्यम में भारतीयाभियां ने इस प्रोत्साहन पर हस्ताक्षर किए हैं यही माध्यम और वैधता ही है जिसे कि वह इस अधिसमय में प्राप्तमर्यादा अन्त स्वाप्तिक किया गया हो।

नई हिन्दी में यह एक हजार तो मौ प्रियांक के जूलाई, मास के 19वें दिन को हिन्दी, कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में सूलत हो—शी प्रतियों में किया गया, इसके मर्मी पाठ मासानन्द प्रमाणिक होंगे। तीनों पाठों में अन्तिम की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से कोरिया गणराज्य की सरकार की ओर से
(विश्वनाथ प्रसाद मिश्र)

वन मर्यादा
विदेश मंत्री

भारतीय राजदूतावास
मिश्र

अनुगमन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान का प्रोत्साहन

ग्राहीकृत्याभियां, सुधीर तुकाराम देवारे, कोरिया गणराज्य में भारतीय गणराज्य के विशिष्ट राजदूत और पूर्णस्विकृती और कोरिया गणराज्य के विशेष-कार्य मंत्रालय से अलगरूप संगठन व संघिय वर्गों के महानियेंगक जिन द्वीपों ने, जो अपनी-अपनी संस्कारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राप्तिकृत हैं, आप पर वर्गों के संबंध में दोहरे कराधान के परिधीर और किनीय प्रपर्वकत की रैक्कने के लिए, भारतीय गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच हाए अधिसमय के अनुसमर्थन के दस्तावेजों आदान-प्रदान के प्रयोजनों बैठक की, जिस पर 19 जूलाई, 1945 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया।

उपर्युक्त अधिसमय के अनुसमर्थन के अपनेअपने दस्तावेजों की जाव करने के बाद उन्हें उचित रूप से भी लोगों में पाये जाने पर उनका श्राव के लिए आदान-प्रदान किया गया।

जिसके अधिसमय भी, उन्होंने वर्तमान प्रोत्साहन पर हस्ताक्षर किया है।

मिश्रालय में 1946 के अगस्त, मास के प्रथम दिन, दो प्राप्तियों में सूलत होने से अंग्रेजी भाषा में सम्बन्ध हुआ, दोनों प्रतियों समानतः प्राप्ताणिक होंगी।

भारत।/—

हस्ता।/—

(ए.स. दं. देवारे)

(प्रिय का-बाक)

भारतीय गणराज्य की सरकार
की ओर से

कोरिया गणराज्य की सरकार
की ओर से

[सं ६९३७-का में ५०१/२२/७३ ता का]

वि. गु. प्रद्युम्न संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 26th September, 1986

NOTIFICATION

INCOMB TAX

G.S.R. 1111(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged, as required by paragraph 1 of Article 29 of the said Convention, on 1st August, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article I

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are :

(a) In the case of Korea :

- (i) the income tax ;
- (ii) the corporation tax; and
- (iii) the inhabitant tax ;

(hereinafter referred to as "Korean tax") ;

(b) In the case of India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ;

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;

(hereinafter referred to as "Indian tax") .

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The Competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention unless the context otherwise requires :

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Korea or India as the context requires ;

(b) the term "tax" means Korean tax or Indian tax, as the context requires ;

(c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons which is treated as an entity for tax purposes ;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes ;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;

(f) the term "competent authority" means, in the case of Korea, the Minister of Finance or his authorised representative; and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorised representative ;

(g) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in the Contracting State ;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of this Convention by either Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of the Convention the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him, if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests can not be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubt the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses a building site, a construction assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than nine months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising goods or merchandise or for collecting information for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, the supply of information, scientific research, or any other activity, if it has a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, if a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 6 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment by virtue of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the ownership, use or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 5 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be effected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

3. For the purposes of this Article the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns directly at least 20 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term 'dividends' as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article:

(a) where the interest is paid to a bank carrying on a bona fide banking business which is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest;

(b) where the interest is paid to the Government of one of the Contracting States or a political sub-division or local authority or the Central Bank or the Export-Import Bank of that State, it shall not be subjected to tax by the State in which it arises.

4. The term "interest" as used in this Article mean income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claims in respect of which the interest is "effectively connected" with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultative nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services and paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by the permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Capital gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of immovable property, may be taxed in the State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purposes of performing professional services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in the other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ship and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property, other than those mentioned in preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. The term "alienation" shall mean alienation in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the "previous year" or "taxation year" concerned, as the case may be; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxable only in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES AND REMUNERATION OF TOP-LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a Company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or athletes if their visit to that State is substantially supported from the public funds of the other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof.

Article 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 20

GOVERNMENT FUNCTIONS

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of service rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Article 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea and the Korea Trade Promotion Corporation and in the case of India, by the Reserve Bank of India and the EXIM Bank of India, and by organizations recognized by and agreed between the competent authorities of the Contracting States.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding one million and one hundred thousand Korean Won or its equivalent in Indian currency during any "previous year" or the "taxation year", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which is recognised by the competent authority in that other State, visits that other State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution, shall be exempt from tax in that other State on his remuneration for such teaching or research, for a period not exceeding two consecutive years from the date of his first arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows :

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle hereof), the Indian tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within India shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within India bears to the entire income subject to Korean tax.

2. For the purposes of paragraph 1, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indian tax which would have been payable in accordance with Indian tax laws but for the exemption or reduction of Indian tax in accordance with the laws relating to incentives for the promotion of economic development in India which were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may subsequently be introduced in India in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States, provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends referred to in paragraph 2 (a) of Article 11 an amount of 15 per cent of the gross amount of such dividends and, in the case of dividends referred to in paragraph 2 (b) of Article 11 an amount of 20 per cent of the gross amount of such dividends;
- (b) in the case of interest referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest and in the case of interest referred to in paragraph 3 (a) of Article 12 an amount of 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such royalties.

3. In the case of a resident of India, double taxation shall be avoided as follows :

Subject to the provisions of Indian tax law regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof), the Korean tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Korea and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Korea shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Indian tax which the income from sources within Korea bears to the entire income subject to Indian tax.

4. For the purposes of paragraph 3, the term "Korean tax payable" shall be deemed to include the amount of Korean tax which would have been payable in accordance with Korean tax laws but for the exemption or reduction of Korean tax in accordance with the laws relating to incentives for the promotion of economic development in Korea which were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may subsequently be introduced in Korea in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States, provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends referred to in paragraph 2 (a) of Article 11 an amount of 15 per cent of the gross amount of such dividends and, in the case of dividends referred to in paragraph 2 (b) of Article 11 an amount of 20 per cent of the gross amount of such dividends;
- (b) in the case of interest referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest and in the case of interest referred to in paragraph 3 (a) of Article 12 an amount of 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties referred to in paragraph 2 of Article 13 an amount of 15 per cent of the gross amount of such royalties.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be constituted as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident

or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. This case must be presented within three years from the first Notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself about to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State.

However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court, proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents and consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Seoul as soon as possible.

The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratification.

2. This Convention shall have effect:

(a) in Korea:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention is initialled; and
- (ii) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention is initialled.

(b) in India:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention is initialled; and
- (ii) in respect of other taxes for previous years beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention is initialled.

Article 30

TERMINATION

The Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in Korea:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

(b) in India:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of other taxes for previous years beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 19th day of July one thousand nine hundred and eighty five on three original copies each in the Hindi, Korean and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the

Republic of India

(VISHWANATH PRATAP SINGH)
MINISTER OF FINANCE

For the Government of
the Republic of Korea

(WON KYUNG LEE)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the convention.

1. In respect of subparagraph (a) of paragraph 3 of Article 2 of the Convention, it is understood that the Convention shall also apply to the Korean defence tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax.

2. For the purposes of Articles 8 and 9 of the Convention, it is understood that:

- (i) interest on funds connected with the operation of aircraft and ships in international traffic shall also be regarded as profits from the operation of such aircraft and ships; and
- (ii) in respect of the operation of aircraft and ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of India, shall also be exempt from the value added tax in Korea and, if an enterprise of Korea, shall also be exempt from any tax similar to the value added tax in Korea, which may hereafter be imposed in India.

3. In respect of Article 9 it is understood that the provisions of its paragraphs 1 and 2 shall apply in respect of shipping transport carried on or after the taxation year in which an agreement related to shipping transport between the Contracting States or their authorized nominees is concluded and becomes effective.

It is further understood that until an agreement relating to shipping transport between the Contracting States or their authorised nominees enters into force, paragraph 2 shall read as follows: "profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 90 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State."

4. In respect of paragraphs 2 and 4 of Article 24, it is understood that the provisions of those paragraphs shall apply for the first 5 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

In witness whereof, the undersigned have signed the present protocol which shall have the same force and validity as if it were inserted word by word in the Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 19th day of July of the year one thousand nine hundred and eighty five on three original copies each in the Hindi Korean and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India

(VISHWANATH PRATAP SINGH)
MINISTER OF FINANCE

For the Government of the Republic of Korea

(WON KYUNG LEE)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

भारत य राजदूतावास, दिल्ली
EMBASSY OF INDIA
SEOUL

PROTOCOL OF

EXCHANGE OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION

The undersigned, Sudhir Tukaram Devare, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Republic of Korea, and Shin Kee-Bock, Director-General of the International Organizations and Treaties Bureau, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, being duly authorized by their respective Governments, have met for the purpose of exchanging the Instruments of Ratification of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at New Delhi on 19 July 1985.

The respective Instruments of Ratification of the aforementioned Convention having been examined and found to be in good and due form, the exchange thereof took place this day.

In witness whereof, they have signed the present Protocol.

Done in two originals in the English language, both being equally authentic, at Seoul this first day of August, 1986.

Sd/- Illegible
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd/- Illegible
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA
[No. 6937-F No. 501/22/73-FTDI
V. U. ERADI, Jt. Secy.